Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 7-12

हिमालयन राष्ट्र 'नेपाल' में महाशक्तियों के रणनीतिक निहितार्थ : एक समीक्षात्मक अध्ययन

अभिषेक भारती

प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र, उदित नारायण इंटर कॉलेज, पडरौना, कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)
शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय (सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)

शोध सारांश

यह लेख हिमालयन राष्ट्र 'नेपाल' में भारत, चीन व अमेरिका के रणनीतिक निहितार्थ तथा पाकिस्तान समर्थित अनैतिक तत्वों के नेपाल में बढ़ते प्रभाव का विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है। इस लेख में नेपाल में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत चीन व भारत की प्रतिद्वंद्वी विदेश नीति की भी समीक्षा की गई है। विगत वर्षों में नेपाल की विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत समदूरी सिद्धांत आधारित हैं, जिसके तहत नेपाल अपने दोनों प्रमुख पड़ोसी भारत व चीन के साथ समान सम्बन्ध स्थापित कर अपनी आवश्यकताओं में दोनों देशों के सहयोग को प्राप्त करना चाहता है। नेपाल की विशेष भू-राजनीतिक स्थिति व भारत-नेपाल अधिकांश छिद्रिल सीमा के कारण ही हिमालयन राष्ट्र में पाकिस्तान समर्थित अनैतिक तत्व भी निरंतर प्रभाव विस्तार हेतु प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त उक्त लेख में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत- अमेरिका रणनीतिक समन्वय से आशंकित चीन द्वारा दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने से सम्बन्धित भारत की भू-सामरिक नाकेबंदी की नीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। विगत वर्षों में नेपाल में माओवादी विचारधारा व राजनीतिक सत्ता में साम्यवादी दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण नेपाल की परिवर्तित भू-राजनीति के संदर्भ में भारत के समक्ष उत्पन्न प्रमुख रणनीतिक चिंताओं का भी विश्लेषणात्मक अध्ययन उक्त लेख में किया गया है।

संकेताक्षर—*राणा शासन, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटिजी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एशिया रिअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट*

प्रस्तावना

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महाशक्तियों की परिधि में स्थित छोटे राज्यों की आर्थिक व राजनीतिक संप्रभुता सीमित तथा विदेश नीति रक्षात्मक यथार्थवाद पर आधारित होती है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महाशक्तियों के व्यवहार व रणनीति के आधार पर छोटे राष्ट्रों को अपनी विदेश नीति समायोजित करनी पड़ती है। किसी भी देश की भू-रणनीतिक स्थिति उसकी विदेश नीति को निर्धारित करती है। नेपाल की विशेष भू-राजनीतिक स्थिति के कारण ही चीन और भारत की तुलना में क्रमशः 68 गुना और 23 गुना छोटा राष्ट्र[1] वर्तमान में दक्षिण एशिया की राजनीति का केंद्र बिंदु तथा विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता का शिकार है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग कि.मी. तथा जनसंख्या 30 मिलियन है (दुनिया का 45वां सबसे बड़ा राष्ट्र है)।[2] नेपाल, उत्तर में चीन के तिब्बत राज्य और पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में पाँच भारतीय राज्य क्रमशः पश्चिम से पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ लगभग 1751 किमी. की सीमा साझा करता है। नेपाल की विशेष भू-राजनीति स्थिति के कारण भारत, चीन, पाकिस्तान व दक्षिण एशिया के संदर्भ में अमेरिकी रणनीति में नेपाल को प्राथमिकता तथा राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उसे वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। नेपाल में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका व भारत के सामरिक महत्व अलग-अलग हैं, जिसका उक्त लेख में विश्लेषणत्मक उल्लेख है।

ISSN 2348-3857

भारत और चीन के साथ नेपाल के रिश्ते 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के बाद परिवर्तित हुए। माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में 1949 में कम्युनिस्ट चीन की स्थापना तथा 1950 में तिब्बत अधिग्रहण के समयांतर में नेपाल की भू-रणनीतिक स्थिति में भी काफी परिवर्तन आया। 1950 के पहले तक नेपाल में प्रभावी राजनीतिक शक्ति राणा परिवार के हाथों में थी, जिन्होंने वंशानुगत रूप में काम करते हुए देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। वंशानुगत राणा शासन को 1951 में समाप्त कर नेपाल एक वास्तविक राष्ट्र-राज्य के रूप में उदित हुआ। भारत, नेपाल में लोकतांत्रिक सत्ता की स्थापना का सदैव हिमायती रहा है। नेपाल में लोकतांत्रिक ताकतों के भारत के समर्थन के खिलाफ चीन ने प्रत्यक्षतः राजशाही का समर्थन किया। यही वजह थी कि नेपाल की राजशाही ने दबाव कारक के रूप में अपनी विदेश नीति में चीन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। भारत-नेपाल पारम्परिक संबंधों की पृष्ठभूमि में 1962 के भारत-चीन युद्ध में नेपाल का मौन रहना, भारत की रणनीतिक असफलता व नेपाल-चीन प्रगाढ होते संबंधों का पर्याय था। राजा महेंद्र ने नेपाल की राजनीति में भारत के प्रभाव के खिलाफ चीन को एक संतुलनकारी व परोपकारी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया तथा भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को सम्मिलित करने के बाद राजा महेन्द्र ने चीन के इस अधिप्रचार 'प्रोपेगेंडा' का पुरजोर समर्थन किया कि नेपाल, भारत की साम्राज्यवादी नीति का अगला लक्ष्य है। चीन के प्रभाव में ही नेपाल के सम्राट ने "नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित" करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि यह प्रयास असफल रहा किंतु फिर भी यह प्रस्ताव भारत पर एक तरह का दोषारोपण था कि भारत, नेपाल की सम्प्रभुता व अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। 1990 के बाद माओवादियों के शस्त्र संघर्ष से नेपाल की राजनीति में परिवर्तन आया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चीन ने माओवादी विद्रोहियों (लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना से सम्बन्धित मांग) को कुचलने के लिए 1990 के दशक में राजशाही को सैन्य व आर्थिक मदद की किंतु आज नेपाल के कम्युनिस्ट दल उसी बीजिंग को अपना सबसे बड़ा हिमायती मानते हैं।[3]

21वीं सदी की परिवर्तित परिस्थितियों में नेपाल के संदर्भ में चीन के दो प्रमुख हित हैं। प्रथम, नेपाल के प्रमुख साम्यवादी दल सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-माओ के बीच राजनीतिक एकजुटता स्थापित करना व द्वितीय, तिब्बत से सम्बन्धित दक्षिणेत्तर सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चूंकि नेपाल, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जो चीन की दक्षिण एशिया नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तिब्बत में किसी भी प्रकार के चीन विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नेपाल का सक्रिय सहयोग तथा भारत की भू-सामरिक नाकेबंदी करने में चीन, नेपाल को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।[4] विगत वर्षों में भारत और नेपाल के मध्य 1950 के शांति व मित्रता संधि की समीक्षा, सीमा अतिक्रमण विवाद (लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, सुस्ता), आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप, सीमा नाकाबंदी आदि विवादों से उत्पन्न अविश्वास ने नेपाल में चीन को प्रभाव विस्तार हेतु एक अवसर प्रदान किया। विगत वर्षों में बीजिंग ने आर्थिक व राजनीतिक निवेश के माध्यम अपने छोटे पड़ोसियों से भारत के आंशिक विवाद/असहमति के खिलाफ स्वयं को एक परोपकारी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है। नेपाल अपनी सीमित आवागमन सुविधा के बावजूद चीन को दक्षिण एशिया क्षेत्र में लिंक स्थापित करने में गेटवे "प्रवेश मार्ग" प्रदान करता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े बाजार तक पहुँच स्थापित करने में मददगार है। चीन ने पूर्व में नेपाल के प्रत्यक्षतः आंतरिक मामलों में 'हस्तक्षेप न करने' की नीति अपनाई थी किंतु 2017 में प्रमुख वामपंथी दलों के गठबंधन और 2020 की राजनीतिक अस्थिरिता के वक्त बीजिंग नेपाल की आंतरिक राजनीति में भी सक्रिय प्रतिभागी रहा है। सम्भवतः यह इसलिए कि वैचारिक समानता वाले दलों के सत्ता में होने से बीजिंग के रणनीतिक हितों को मजबूती प्राप्त होगी। कॉम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में काबिज होने के साथ नेपाल-चीन पारगमन समझौता, अवसंरचनात्मक विकास हेतु बीआरआई प्रोजेक्ट, नेपाल-चीन ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के विस्तार सम्बन्धित झांगमू/खासा बंदरगाह, जिलांग/किरंग बंदरगाह, काठमांडू-पोखरा-लुम्बिनी रेलवे प्रोजेक्ट, अरंकिनो तथा रसुवागढी हाईवे, जिलॉन्ग/किरंग से काठमांडू के मध्य सुगम आवागमन सम्बन्धित सुरंग निर्माण जैसी प्रमुख लिंक परियोजनाओं के माध्यम से दोनों देश दुर्गम परिवहनीय मार्गों को सुगम परिवहनीय मार्गों में बदलने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं।[5] भौगोलिक कारणों से चीन-नेपाल लिंक सड़क का निर्माण भारत की तुलना में जटिल है किंतु वर्तमान प्रौद्योगिकी के युग में भौगोलिक चुनौतियों को भी बौना साबित किया जा सकता

है। चीन-नेपाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट समझौता 2016 इसी दिशा में एक प्रयास है। यह समझौता नेपाल को सात चीनी बंदरगाहों के माध्यम से तीसरे देश से आयात-निर्यात की अनुमति देता है। निश्चित रूप से भारत पर व्यापारिक आवागमन सम्बन्धित निर्भरता को कम करने वाला यह समझौता भू-राजनीतिक व भू-आर्थिक रूप से नेपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2017 में बीआरआई में नेपाल की भागीदारी का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा चीन के बंदरगाहों तक पहुँच स्थापित करना था।[6] किंघाई तिब्बत रेलवे विस्तार, ल्हासा-शिगात्से लिंक परियोजना तथा बीआरआई के तहत प्रस्तावित सिगात्से-केरुंग-काठमांडू रेलवे परियोजना तथा चीन-नेपाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट आदि नेपाल के आर्थिक विकास तथा समुद्री परिवहन में भारत का विकल्प देने का प्रयास है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा से झांगमू तथा कोडारी से काठमांडू चीन-नेपाल फ्रेंडशिप हाईवे दोनों देशों के मध्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। यद्यपि चीन के माध्यम से नेपाल का व्यापार खर्चीला व आवागमन में दुर्गम है किंतु विगत वर्षों में अवसंरचनात्मक लिंक परियोजनाओ के संदर्भ में तेजी आई है। वर्तमान में चीन, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्रोत है। 2022-23 वित्तीय वर्ष में नेपाल में चीन के निर्यात में 26.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। नेपाल में चीन का निर्यात 1995 में 53.4 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 तक 171 मिलियन डॉलर हो गया है।[7]

चीन की नीति व्यवहारिक यथार्थवाद पर आधारित है, जिसने अपने छोटे पड़ोसी पर प्रभाव विस्तार के नैतिक/अनैतिक समस्त साधनों का प्रयोग किया है। चीन द्वारा विभिन्न देशों के साथ आर्थिक गलियारा व पारगमन लिंक (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा), तिब्बत व नेपाल के मध्य ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशल कनेक्टिविटी नेटवर्क तथा विभिन्न बंदरगाह (ग्वादर, हबनटोटा, क्यूप्यूप) तक पहुँच स्थापित करना, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत व अमेरिका के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी रणनीति का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप में भौतिक प्रभाव विस्तार से सम्बन्धित चीन की महत्वाकांक्षी 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई। उक्त परियोजना के माध्यम से चीन विश्व बाजार में अपनी पहुँच और दक्षिण एशिया में भारत की नाकेबंदी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। प्रारम्भ में नेपाल सरकार को उम्मीद थी कि ओबीओआर जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाएँ अनेक पारगमन बिंदुओं तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ विकास रणनीतियों को संरेखित और समन्वित करने, निवेश को बढ़ावा देने व रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मददगार साबित होंगी किंतु समस्या यह है कि बी.आर.आई. से सम्बन्धित योजनाओं का वित्तपोषण अधिकांशतः उच्च ब्याजदर वाले चीन के व्यापारिक लोन के माध्यम से है। जबकि नेपाल विश्व बैंक से तुलनात्मक रूप से कम ब्याजदर पर लोन प्राप्त कर सकता है। सम्भवतः यही वजह है कि नेपाल में वैचारिक समानता वाले वामपंथी दलों के सत्ता में होते हुए भी बीआरआई के संदर्भ में विशेष प्रगति नहीं हुई है। 2019 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के दौरान बीआरआई के तहत चयनित परियोजनाओं की संख्या पैंतीस से घटकर नौ कर दी गई है। विगत वर्षों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत परियोजनाओं की स्वीकृत को लेकर नेपाल के ढुलमुल रवैया तथा पूर्ववर्ती देउबा सरकार द्वारा अमेरिका की महत्वाकांक्षी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) परियोजना की संसदीय स्वीकृति बीजिंग के लिए चिंतनीय है।

अमेरिका की इंडो- पैसिफिक स्ट्रैटिजी के तहत 2018 में पहली बार नेपाल को एक उभरते रक्षा भागीदार के रूप में उल्लेखित किया गया। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा नेपाल के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहयोग को लेकर 2017 में अमेरिका-नेपाल बहुचर्चित एमसीसी पर हस्ताक्षर हुए। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) गरीब देशों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु 2004 में अमेरिकी काँग्रेस द्वारा शुरु अनुदान योजना है। हिंद महासागर क्षेत्र के सामरिक महत्व व क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु अमेरिका की एशिया प्रशांत नीति में सक्रियता आई है। 2019 में इंडो-यूएस पैसिफिक स्ट्रैटिजी और क्वाड (भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान) का संयुक्त प्रयास हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना है।[8] अमेरिका के लिये एशिया प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व इसलिये भी है क्योंकि यह क्षेत्र वर्तमान में विश्व के आर्थिक व रणनीतिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करने की नीति में अमेरिका-भारत रणनीतिक संरेक्षण में दक्षिण एशिया के देशो का रणनीतिक महत्व है। वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक-दूसरे के सहयोगी बनकर उभर

रहे हैं। अमेरिका ने पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिकी हितों के प्रतिकूल है। भारत 'एक्ट ईस्ट' नीति, आसियान तथा बिम्सटेक के माध्यम से पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को गति प्रदान कर रहा है। अमेरिका एशिया केंद्रित नीति केवल सैनिक विस्थापन की नीति नहीं है, बल्कि एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रभावी करने की नीति है, नेपाल में एमसीसी परियोजना इस दिशा में ही एक प्रयास है।[9]

भारत के संदर्भ में हिमालयन राष्ट्र का रणनीतिक महत्व इसलिए और भी है क्योंकि नेपाल पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने वाले सिलिगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है। नेपाल में किसी भी प्रकार की सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता अथवा विरोधी तत्वों के सक्रिय होने पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की सुरक्षा तथा उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे बड़े जनसांख्यिकी भाग की सुरक्षा को प्रभावित हो सकती है। भारत के उत्तर-पूर्व 'अरुणाचल प्रदेश' और उत्तर-पश्चिम सीमांत 'लद्दाख' में चीन के साथ सीमा विवाद है। पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सैन्य ठिकानों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उत्पन्न नृजातीय संघर्ष व अलगाववादी सशस्त्र संघर्षों की चिंताजनक परिस्थितियों में यदि नेपाल के साथ भी अविश्वास बढ़ता है तो पाकिस्तान, चीन व नेपाल तथा पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी संगठनो की हिंसक गतिविधियों से भारत के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में भू-रणनीतिक सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त चीन सामरिक हितों के लिए नेपाल में न केवल आर्थिक अपितु सांस्कृतिक व वैचारिक प्रभाव में वृद्धि हेतु भी प्रयासरत है। चाइना स्टडी सेंटर्स (सीएससी) की अनेक शाखाओं के माध्यम से चीन, नेपाल में (विशेषकर तराई क्षेत्र) अपना वैचारिक व सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा रहा है।[10] वर्तमान में बुटवल, बनेपा, संखुवासभा, पोखरा, विराटनगर, मोरंग, सुनसारी, चितवन, नेपालगंज और लुंबिनी में सीएससी की शाखाएँ स्थित हैं।[11] इन सीएससी सेंटर्स के माध्यम से चीन, भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत विरोधी भावना को निरंतर बढ़ावा दे रहा है।

नेपाल में चीन के बढ़ते सामरिक प्रभाव के बावजूद भी भारत, नेपाल में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से सबसे बड़ा हितधारक है। दोनों देशों का एक बड़ी जनसांख्यिकी भाग एक समान सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों को मानता है। भौगोलिक सुगमता के कारण नेपाल का अधिकांश व्यापार भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से होता है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारत-नेपाल सीमा पर 27 प्रवेश/ निकास बिंदु तथा अधिकांश व्यापार कोलकाता-हल्दिया और विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से होता है। इसके अलावा, बांग्लादेश के साथ नेपाल का व्यापार भी भारत के पारगमन मार्गों से ही होता है। भारत-नेपाल आर्थिक सम्बंध की प्रगाढता इस तथ्य के माध्यम से आसानी से समझी जा सकती है कि जब दुनिया भर की अधिकांश सीमाएं बंद थी, उस वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेपाल कस्टम के आंकड़ों के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। किंतु 2016 व 2023 में भारत में क्रमशः 500, 1000, 2000 की मुद्रा विमुद्रीकरण से उत्पन्न कठिनाइयो के कारण वर्तमान में नेपाल के बाजार में 100 रु से अधिक की भारतीय मुद्रा का प्रयोग अवैध है, जिससे निश्चित ही भारत-नेपाल व्यापार व सीमावर्ती नागरिकों की क्रय क्षमता प्रभावित हुई है। विगत वर्षों में विद्युत व्यापार भारत-नेपाल सम्बन्धों में एक प्रमुख कडी साबित हुआ है। नेपाल के प्रमुख पडोसी राष्ट्र चीन, भारत व बांग्लादेश में ऊर्जा खपत दिन-प्रतिदिन बढ रही है, जबकि नेपाल में घरेलू और औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त भी व्यापार हेतु विद्युत क्षमता उपलब्ध है। ऐसे में यदि 2030 तक 'हाइड्रो 20' के तहत नेपाल अपनी कुल क्षमता के 20 प्रतिशत विद्युत का भी उत्पादन कर पाता है तो यह नेपाल की आर्थिक क्षमता हेतु गेमचेंजर होगा।[12] 2014 के बाद से ही भारत, क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, सीमापार विद्युत बाजार पहुँच तथा संस्थागत तकनीकी व प्रौद्योगिकी निवेश में सक्रियता व तीव्रता के माध्यम से नेपाल के जलविद्युत क्षेत्र में साझा सहयोग/समंवय व व्यापार क्षेत्र में सक्रिय हितधारक है। स्पष्ट है कि यदि ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर लिया जाए तो भारत, चीन व बांग्लादेश जैसे पड़ोसी एशियाई देश नेपाल की उपयोग से अतिरिक्त उत्पादित विद्युत को आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। जून 2023 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नेपाल द्वारा बांग्लादेश को 50 मेगावाट बिजली निर्यात समझौता इसी दिशा में एक प्रयास है।[13]

भारत-नेपाल सम्बंध में एक नकारात्मक कारक के रूप में पाकिस्तान का उद्भव मार्च 1960 में नेपाल-पाकिस्तान राजनयिक संबंधों की शुरुआत के साथ हुआ। 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही खालिस्तानी, कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत-नेपाल अधिकांश छिद्रिल सीमा ने एक अवसर प्रदान किया। खालिस्तानी आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स आदि खालिस्तानी समूह व जैश-ए-मोहम्मद, अलकायदा व आई.एस.आई.एस. आदि आंतकवादी संगठनों के भारत में अव्यवस्था हेतु नेपाली मार्गों के अनेक प्रमाण मिले हैं।[14] नेपाल तेजी से पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस द्वारा की गई भारत विरोधी गतिविधियों के लिए एक केंद्र बन गया। आई.एस.आई द्वारा बडे पैमाने पर आर.डी.एक्स और अवैध भारतीय मुद्रा की नेपाल के माध्यम से भारत में तस्करी की जाती है। विगत वर्षों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सैन्य एजेंसियों द्वारा उठाए गए सख्त सुरक्षा उपायों के कारण जम्मू-कश्मीर को सीधे धन भेजना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की आई.एस.आई अवैध हथियार व मुद्रा की तस्करी हेतु भारत-नेपाल छिद्रिल सीमा का उपयोग कर रही है। मीडिया रिपोर्टों को यदि आधार माना जाए तो सीमावर्ती जिलों के व्यापारी व युवा वर्ग प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से कैश कोरियर की भूमिका निभा रहे हैं।[15] इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस की काठमांडू में हमेशा से मौजूदगी रही है किंतु वर्तमान में सेवानिवृत्त नेपाली सुरक्षा बलों के अधिकारियों को आई.एस.आई. के खुफिया तंत्र से सम्मिलित करने के प्रयास सम्बन्धित मीडिया रिपोर्ट ज्यादा चिंताजनक है।[16] इसके अतिरिक्त पाकिस्तान वित्तपोषित वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने हेतु कई अनैतिक मदरसों का कार्यक्षेत्र भारत-नेपाल सीमावर्ती जिले में हैं, जिसके माध्यम से निश्चित ही सामाजिक ताने-बाने में भारत विरोधी भावना बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

नीतिगत सुझाव

विगत वर्षों में नेपाल का उत्तरी पड़ासी राष्ट्र चीन अपने सामरिक हितों हेतु हिमालयन राष्ट्र में प्रभाव विस्तार के प्रयासों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है कि सीमाबंदी, विमुद्रीकरण से उत्पन्न समस्याएँ गोरखा नियुक्ति सम्बन्धित विवाद आदि से सम्बन्धों में उत्पन्न अविश्वास को सांस्कृतिक व भावनात्मक जुड़ाव व आर्थिक सहयोग तथा संवाद तंत्र स्थापित कर समाप्त किया जाए। एक स्थलरुद्ध राष्ट्र के रूप में नेपाल को एक स्पष्ट व स्वतंत्र कूटनीति का पालन करते हुए दोनों प्रमुख पड़ोसियों का संतुलनकारक के बजाय सहयोगी कारक के रूप में इस्तेमाल करके ही अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नेपाल को वैश्विक शक्तियों के साथ अपने संबंधों के विविध पहलू का सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए तथा राजनैतिक व रणनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए नेपाल के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप नीति व निर्णय का निर्माण करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका भू-राजनीतिक महत्व और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण नेपाल में प्रभाव विस्तार हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। भारतए चीन के साथ संतुलन बनाए रखते हुए विकास और समृद्धि के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नेपाल के लिए प्रमुख चुनौती है, ऐसे में नेपाली विश्लेषकों का विचार है कि चाहे वह अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट हो या चीन का बीआरआईए नेपाल के हित में यह है कि वह योग्यता के आधार पर किसी भी समझौते को स्वीकार या अस्वीकार करे। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारत विरोधी तत्वो की बढती सक्रियता को नियंत्रित करना नेपाल के समक्ष सबसे प्रमुख सुरक्षा चुनौती है, क्योंकि अस्थिर तराई क्षेत्र न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि नेपाल की एकता व अखंडता के लिए भी खतरनाक और भारत के साथ उसके पारम्परिक सम्बंधो को भी क्षति पहुँचाएगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नेपाल-चीन अथवा भारत-नेपाल संबंध का भविष्य नेपाल की कूटनीति तथा चीन-भारत संबंध की प्रकृति पर काफी हद तक निर्भर करता है।

सन्दर्भ सूची

1. कुमार, सतीश, इंडिया-चाइन मेजर डिस्प्यूट्स नेपाल, भूटान एंड तिब्बत, इंदु बुक्स सर्विस, न्यू देहली, 2017, पी.पी. 6-7
2. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वर्ल्डमीटर्स ऑफ इन्फो/वर्ल्ड-पोपुलेशन/नेपाल-पोपुलेशन/
3. उपाध्याय, एस., नेपाल एंड दि जियो-स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन चाइन एंड इंडिया, रॉललेज पब्लिकेशन, 2012, पी.पी. 133-146

4. गैंग, डी., तिब्बत केन भी गेटवे टू इंडियन ट्रेड, ग्लोबल टाईम्स, एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ग्लोबलटाईम्स डॉट सीएन/पेज/201610/1010977 डॉट एसएचटीएमएल, अक्टूबर 12, 2016
5. ज्वॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन नेपाल एंड दि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना-मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेपाल एमओएफए, एचटीटीपीएसः//एमओएफए डॉट जीओवी डॉट एनपी/ज्वॉइंट-स्टेटमेंट-बिटवीन-नेपाल-एंड-दि-पीपुल्स-रिपब्लिक-ऑफ-चाइना-2/, अक्टूबर 13, 2019
6. एचटीटीपीएसः//एमओएफए डॉट जीओवी डॉट एनपी/नेपाल-चाइना-रिलेशंस/
7. एचटीटीपीएसः//ओईसी डॉट वर्ल्ड/ईएन/प्रोफाइल/बाइलेटरल-कंट्री/
8. लूथरा, जी., दि न्यू यूएस इण्डो-फैसेफिक स्ट्रैटेजीः बेलेसिंग कन्टीन्यूटी विद न्यू एंड इवोल्विंग एनवायरमेंट. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑरफोनलाइन डॉट ओआरजी/एक्सपर्ट-स्पीक/दि-न्यू-यूएस-इण्डो-फैसेफिक-स्ट्रैटेजी/ ओआरएफ, मार्च 15, 2022
9. पिल्लई, आर., इंडियाज़ प्लेस इन दि न्यू यूएस इण्डो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी, एचटीटीपीएसः//दिइण्डोमेट डॉट कॉम/2022/20/इंडियाज़-प्लेस-इन-दि-न्यू-यूएस-इण्डो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी/ ओआरएफ, फरवर 24, 2022
10. भट्टाचार्य, ए., चाइनाज इनरोड्स इनटू नेपालः इंडियाज़ कनसर्नस, आईडीएसए, एचटीटीपीएसः//आईडीएसएस डॉट इन/नोड/756/117, 2009.
11. टीकू, तनिया, इज इंडिया लूजिंग नेपाल एज़ ए लॉयल नेबर टू चाइना? बीडब्ल्यू बिजनेसवर्ल्ड, एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बिजनेसवर्ल्ड डॉट इन/एएमपी/आर्टिकल/इज-इंडिया-लूजिंग-नेपाल-एज़-ए-लॉयल-नेबर-टू-चाइना-/12-04-2018-146220/, अप्रैल 12, 2018.
12. गुणातिलके, हेराथ एंड प्रियंथा विजयातुंगे, डेविड रोलाण्ड-होल्स्ट, हाइड्रोपावर डेवलेपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन नेपाल, एडीबी साउथ एशिया वर्किंग पेपर सीरिज, नं. 70, जून, 2020, पीपी 5-6.
13. एमबेस्सी ऑफ इंडिया, काठमांडू, नेपालः प्रेस रिलीजः एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंडेएमकाठमांडू डॉट जीओवी डॉट इन/न्यूज-लेटर-डीटेल/?आईडीत्र253
14. मिसयूज ऑफ नेपाल्स टेरिटरी बाइ पाकिस्तान्स इंटेलीजेंस एजेन्सीस टू फोमेंट टेरेरिज्म, यूरोपियन फाउण्डेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ईएफएसएएस डॉट ओआरजी/पब्लिकेशन्स/स्टीज-पेपर्स/मिसयूज-ऑफ-नेपा-टेरिटरी-बाइ-पाकिस्तान-इंटेलीजेंस-एजेन्सीस-टू-फोमेंट-टेरेरिज्म/, एक्ससेज्ड ऑन 25 मई, 2023 एट 11 एएम.
15. राजन, मुकेश, आईएसआई फंडिंग टेरर इन वैली वाया नेपालः इनटेल. दि ट्रिब्यून. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ट्रिब्यूनइंडिया डॉट कॉम/न्यूज/जे-के/आईसीआई-फंडिंग-टेरर-इन-वैली-वाया-नेपाल-इनटेल-225408, मार्च 14, 2021.
16. कुमार, नवरतन, आईएसआई बैक्ड ग्रुप्स इन नेपाल इनटेनसिफी एंटी-इंडिया एक्टीविटीज, दि संडे गार्डियन, एचटीटीपीएसः//संडेगार्डियनलाइव डॉट कॉम/न्यूज/आईएसआई-बैक्ड-ग्रुप्स-नेपाल-इनटेनसिफी-एंटी-इंडिया-एक्टीविटीज, जून 27, 2020.